

हैदराबाद घोषणा

मई 6, 2006

एडीबी भारत और प्रशांत छोड़ो!

हम 100 से अधिक संघर्ष समूह, जनांदोलन और जन संगठन हैदराबाद में आयोजित एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की 39वीं वार्षिक गवर्नर्स बैठक के विरोध में 4 दिनों के लिए जमा हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (आईएफआईज) और विश्व व्यापार संगठन के साथ-साथ एडीबी भी साम्राज्यवाद के विभिन्न संस्थानिक औजारों में से एक है। उपनिवेशवाद को आजकल विकास के उस नव-उदारवादी मॉडल के जरिये लाया जा रहा है, जिसने अपने लाभ के लिए दक्षिणी गोलार्द्ध के संसाधन सम्पन्न देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन को तेज कर दिया है। इस मॉडल ने राष्ट्र-राज्यों को कर्ज के कुएं में ढकेलते हुए अलाभकारी नीति-सुधार की शर्तों पर मिलने वाली सहायता लेने पर मजबूर कर दिया है। यह मॉडल व्यापार-असंतुलन को बढ़ावा दे रहा है। यह मॉडल हमारे लोकतांत्रिक दायरे, प्रक्रियाओं और संस्थानों को भी तोड़ता-मरोड़ता है। यह मॉडल राष्ट्रीय व जन-सुरक्षा के नाम पर हमारे समाजों के साथ अकथनीय हिंसक रवैया अपनाता है। यह पूरे क्षेत्र के लोगों के लगातार बढ़ाहाल होने और हाशिये पर चलते जाने का मुख्य कारण है। विकास का यह मॉडल सैन्यीकरण को बढ़ावा देता है, आत्म-निर्णय के जनांदोलनों पर राज्य द्वारा किये जाने वाले दमन को वैधता प्रदान करता है और मानवाधिकारों के हनन के लिए उकसाता है। इस मॉडल से सर्वाधिक प्रभावित लोगों में महिलाएं, देशज समुदाय, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीब लोग शामिल हैं।

हम प्रण करते हैं कि हम –

- 1 साम्राज्यवाद के खिलाफ जारी संघर्ष को व्यापक बनाने और तेज करने के लिए विभिन्न संघर्ष समूहों, जनांदोलनों और समुदायों को गोलबंद करेंगे।
- 2 अपने समुदायों, समाजों, अर्थव्यवस्थाओं, संस्थानों और सरकारों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की घुसपैठ को रोकेंगे; एडीबी प्रमुख द्वारा निजी उद्योग में आरक्षण का विरोध करने की निंदा करेंगे।
- 3 खास क्षेत्रों के साम्राज्यवादी सिद्धांत और ग्राम सभाओं/समुदायों जैसे आम क्षेत्रों के निजीकरण का विरोध करेंगे।
- 4 हमारी प्रगति व विकास की धुरी राष्ट्रीय और सार्वजनिक संस्थाओं को महत्व नहीं दिये जाने का विरोध करेंगे।
- 5 विकास व शासन के अपने तौर-तरीके और अपनी चाल तय करने के जन अधिकारों का हम समर्थन करेंगे।
- 6 महिलाओं, देशज, दलित, सीमांत पर खड़े व खतरे में जी रहे समुदायों और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे।
- 7 पर्यावरण और जीविका के संसाधनों के जन-अधिकारों को मजबूत बनायेंगे। जिन लोगों का जीवन इन संसाधनों पर निर्भर करता है, उनका इन संसाधनों के इस्तेमाल पर अधिकार होना चाहिए।
- 8 राज्य और बाजार को लोकतांत्रिक बनाने के लिए सक्रिय रहेंगे, ताकि वे अपनी जनता की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं के प्रति जवाबदेह बनें।
- 9 इस पूरे क्षेत्र के जनांदोलनों और जन संगठनों द्वारा लोकतंत्र, संप्रभुता, आत्म-निर्णय और स्व-शासन के अधिकार को हासिल करने के लिए जारी प्रयासों का हम समर्थन करेंगे।
- 10 उस आर्थिक व्यवस्था का विरोध करेंगे, जो सैन्य युद्ध की मशीनरी और भारी-भरकम रक्षा बजट के लिए धन मुहैया कराती है। हम अ-सैन्यीकरण की प्रक्रिया को तेज करेंगे, जिसमें भारत के उत्तर-पूर्व और अन्य स्थानों में लागू आर्म्ड फोर्स सस्पेंशन पावर्स एक्ट (एपीएसएफए) और अन्य कठोर कानूनों को हटाना भी शामिल है। हम झारखंड, छत्तीसगढ़, भारत के उत्तर-पूर्व और एशिया में अन्य जगहों से भी सैन्य बलों को हटाने की मांग करेंगे।
- 11 आपराधिक और बेकार वित्तीय-पूंजी वाली जीवन शैली को नकारते हैं और मूल्य आधारित स्थायी अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों को स्वीकारते हैं।
- 12 कर्ज आधारित विकास से हटने और अपने पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक संपदा का उपयोग करते हुए वैकल्पिक रास्तों को प्रोत्साहित करने का वायदा करते हैं, ताकि समूची जनता को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर कर्ज से छुटकारा मिल सके। हम मांग करते हैं कि एडीबी अपने कर्जदार देशों के कर्ज को निरस्त करे।

नेशनल एलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एशिया पैसिफिक मूवमेंट ऑन डेट एंड डेवलपमेंट (एपीएमएमडी), फ्रीडम फॉम डेट कोऑलिशन, पीआरआरएम, केआरआरएस, इक्वेशंस, नदी घाटी मोर्चा, रिवर बेसिन फ्रेंड्स, इनवायर्नमेंट सपोर्ट ग्रुप, एडीबी क्विट केरला कम्पेन, इंसाफ, कोर, अर्बन रिसर्च सेंटर, फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ, सिटीजंस कंसर्न फॉर डैम्स एंड डेवलपमेंट, दिल्ली फोरम, समता, नेशनल फोरम ऑफ फॉरिस्ट पीपुल एंड फॉरिस्ट वर्कर्स, माइंस मिनिस्टर्स एंड पीपुल, शाहीन सेंटर, कनज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, वाटर इनीशिएटिव्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, सिविल सोसाइटी इनीशिएटिव ऑन आईएफआईएस (एनई), डीआईसीई फाउन्डेशन, इंटरकल्चरल रिसोर्सिज, एनजीओ टॉस्क फोर्स ऑन एडीबी, नागरिक हितरक्षण समिति, बालकेदारारा हितरक्षण वेदिके, अनिकेतन ट्रस्ट, इंडिया सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लॉ (आईसीएचआरएल), पालनी हिल्स कनजर्वेशन काउंसिल, नेशनल फिशवर्कर्स फोरम, पोलावरम प्रोजेक्ट आंदोलन समिति, नागा पीपुल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स, मूवमेंट अगेस्ट यूरेनियम प्रोजेक्ट्स, सेंटर फॉर इनवायर्नमेंट कंसर्न, अमन वेदिका, आईटीडीएस, पीपुल्स एलायंस सेंटरल ईस्ट इंडिया, जापान सेंटर फॉर सस्टेनेबल इन्वायर्नमेंट एंड सोसायटी (जेएसीएसईएस), सेंटर फॉर इकोनामिक जस्टिस, पैरवी, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, ब्यूरो फॉर ह्यूमन राइट्स, आदिवासी मुक्ति संगठन, पीपुल्स मूवमेंट इन सुबानश्री वैली, कृशक मुक्ति संग्राम समिति, अरुणाचल सिटिजन राइट्स, इंडिजीनस/ट्राइबल पीपुल्स डेवलपमेंट सेंटर, रुरल वालंटियर्स सेंटर, ह्यूमन राइट्स तमिलनाडु इनिशियेटिव, परिसावा बादोकिदारा वेदिका, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, साक्षी ह्यूमन राइट्स वाच, छतरी, झारखंड लेबर यूनियन, दलित वूमन फोरम, नेशनल हाकर्स फेडरेशन, नेटवर्क ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज आर्गनाइजेशन (एनपीडीओ), लोकराज संगठन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, मंथन अध्ययन केंद्र, साउथ एशिया नेटवर्क ऑफ डैम्स, रिवर्स एंड पीपुल्स, ग्रासरूट्स आफ्स, एफआईएमसीओटीएन, डवार्फस पीपुल्स आर्गनाइजेशन, न्यू ट्रेड यूनियन इनिशियेटिव, सेवा, सबला, नेशनल कम्पेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स, वूमन्स कलेक्टिव, बांग्ला प्रैक्सिस, नागरिक उद्योग, कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी डेस्क ऑफ द अदर मीडिया, चश्मा लोकसाथ, नेशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज, ओपन स्पेस, पीपुल्स वॉयस, गंगपुर आदिवासी फोरम, दलित मुक्ति मोर्चा, प्लासीमाडा सॉलिडरिटी कमिटी, पानी कमिटी, कसेलु पालु ग्रुप (पीएनजी), उत्तरान, एओएसईडी, सेव चरा रिवर कम्पेन, गोनो उद्योग फोरम, ग्रीन मूवमेंट ऑफ श्रीलंका और अन्य कई संगठन।

<http://www.asianpeoplesforum.net>

<http://www.insafindia.org>

THE HYDERABAD PLEDGE

May 6, 2006

ADB QUIT ASIA AND THE PACIFIC!

We are over 100 struggle groups, peoples' movements and organisations who gathered together in Hyderabad for 4 days to protest the 39th Annual Governors' Meeting of the Asian Development Bank (ADB). The ADB, along with other International Financial Institutions (IFIs) and the World Trade Organisation, is one of numerous institutional instruments of imperialism. Colonisation is today pursued through the neo-liberal model of development, which has accelerated the appropriation and commodification of natural resources in the resource-rich countries of the South. This model forces nation states into indebtedness and to accept aid with harmful policy reform conditionalities, and widens trade imbalances. It mutilates our democratic institutions, processes and spaces. It perpetrates untold violence on our societies in the name of national and public security. It is the main cause of continuing marginalization and pauperization of our peoples. It fuels the militarization of our polity, legitimizes suppression by the State of peoples' struggles for self-determination, and exacerbates the violation of human rights. Worst affected by these are women, children, indigenous communities, dalits, minority communities and the poor.

We pledge to:

- Unite struggle groups, peoples' movements and communities to broaden and intensify the fight against imperialism.
- Halt the intrusion of IFIs in our communities, societies, economies, institutions and governments; we condemn the ADB President's opposition to the issue of reservation in private industry.
- Fight against privatization of the commons and the imperialist principle of Eminent Domain.
- Prevent the undermining of national and public institutions which are at the core of our growth and development.
- Uphold people's rights to determine their own diversified forms and pace of development and governance.
- Protect the safety and security of women, indigenous, dalit, marginalised and vulnerable communities, and future generations.
- Strengthen peoples' rights to environmental and livelihood resources; those who depend on these resources for survival must have right of governance over them.
- Strive towards democratising the State and markets so that they serve and become accountable to the aspirations and priorities of peoples.
- Support peoples' movements and organisations across the region in their efforts to reclaim people's democracy, sovereignty, self-determination and self-rule to create a better world.
- Oppose an economic order which feeds the military war machinery and bloated defense budgets, and strengthen demilitarisation processes including the withdrawal of the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) and other draconian laws from India's Northeast and elsewhere; we also call for the withdrawal of military forces from Jharkhand, Chattisgarh, the Indian Northeast and elsewhere in Asia.
- Reject the criminal and wasteful finance-capital lifestyle and uphold value based sustainable economies and cultures.
- Move away from debt financed development and promote alternative ways of using our environmental, social and economic wealth, so that all peoples can achieve freedom from debt at local and global levels; we demand that the ADB cancel the debts of its borrowing countries.

National Alliance of Peoples Movements, Narmada Bachao Andolan, Asia Pacific Movement on Debt and Development (APMMD), Freedom from Debt Coalition, Philippines Rural Reconstruction Movement (PRRM), Karnataka Rajya Raitha Sangha (KRRS), Equations, Nadi Ghati Morcha, River Basin Friends, Environment Support Group, ADB Quit Kerala Campaign, INSAF, CORE, Urban Research Centre, Focus on the Global South, Citizens Concern for Dams & Development, Delhi Forum, Samata, National Forum of Forest People & Forest Workers, mines minerals & People, Shaheen Centre, Consumer Protection Forum, Water Initiatives, Consumer Protection Forum, Civil Society Initiative on IFIs (NE), DICE Foundation (Foundation for Dialogues on Indigenous Culture & Environment), Intercultural Resources, NGO Task Force on ADB, Nagarika Hitharakshana Samithi, Balakedarara Hitharakshana Vedike, Anikethana Trust, India Centre for Human Rights and Law (ICHRL), Palni Hills Conservation Council, National Fishworkers Forum, Polavaram Project Andolana Samithi, Naga Peoples Movement for Human Rights, Movement Against Uranium Projects, Centre for Environment Concerns, Aman Vedika, ITDS, Peoples Alliance Central East India, Japan Centre for a Sustainable Environment and Society (JACSES), Center for Economic Justice, PAIRVI, Jharkhand Jangal Bachao Andolan, Bureau for Human Rights, Adivasi Mukthi Sangathan, Peoples Movement in Subansiri Valley, Krishak Mukti Sangram Samithi, Arunachal Citizens Rights, Indigenous/Tribal Peoples Development Center, Rural Volunteers Centre, Human Rights Tamil Nadu Initiative, Parisava Badokidara Vedika, Human Rights Law Network, SAKSHI Human Rights Watch, Chatri, Jharkand Labour Union, Dalit Women Forum, National Hawkers Federation, Net Work of Persons with Disabilities Organisation (NPDO), Lok Raj Sangathan, Consumer Protection Council, Manthan Adhyayan Kendra, South Asia Network of Dams, Rivers & People, Grassroot Options, FIMCOTN, Dwarf People's Organisation, Chatri, New Trade Union Initiative, SEVA, SABALA, National Campaign on Dalit Human Rights, Women's Collective, Bangla Praxis, Nagarik Udyog, Corporate Accountability Desk of The Other Media, Chasma Lok Sath, National Centre for Advocacy Studies, Open Space, Peoples Voice, Gangpur Adivasi Forum, Dalit Mukti Morcha, Plachimada Solidarity Committee, Pani Committee, Kaselu Palu Group (PNG), Uttaran, AOSSED, Save Chara River Campaign, Gono Udyog Forum, Green Movement of Sri Lanka & many others.

<http://www.asianpeoplesforum.net>

<http://www.insafindia.org>